

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/388077410>

Indigenous peoples and local communities from the perspective of sustainable management of natural heritage and mitigation of climate change

Article · January 2023

CITATIONS

0

READS

3

1 author:



Subhash Dande

Kirti M. Doongursee College of Arts, Commerce and Science (Autonomous)

75 PUBLICATIONS 1 CITATION

[SEE PROFILE](#)



International Research Wisdom

(An International Level Refereed, Double Blind Peer Reviewed, Indexed, Multilingual, Interdisciplinary, Monthly Research Journal)

ISSN (P) : 2250-2629 Impact Factor : 6.478 (SJIF)

ISSN (E) : 2320-5466

Issue- I

Vol- I

Month- January- 2023

SUBJECT- Sustainable Development

देशज लोग तथा स्थानीय समुदाय :
प्राकृतिक धरोहर के संघारणीय प्रबंधन एवं जलवायु
परिवर्तन के शमन के परिप्रेक्ष्य में...

डॉ सुभाष भिमराव दोंदे

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे संलग्न, किर्ती कॉलेज (स्वायत्त), दादर (प.) मुंबई -28

सारांश खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए जैव विविधता का संरक्षण अत्यावश्यक है। इसके अलावा वसुंधरा के समस्त आवश्यक कार्यों को बनाए रखने और मानव कल्याण में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक वनों का एक तिहाई से आधा हिस्सा मुख्य रूप से जहाँ-वहाँ सदियों से बसे वन निर्भर मूलनिवासी-देशज लोगों और स्थानीय से समुदायों द्वारा प्रबंधित किया जाता है किन्तु दुनिया की केवल 10 % भूमि के वो कानूनी रूप से मालिक है। देशज लोगों की संस्कृति और आजीविका वन पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई है; जहाँ उनका जैविक अनुकूलन, उनके आध्यात्मिक विश्वासों के साथ, यह मांग करता है कि वे जैवविविधता का संरक्षक बने रहे और वनों का संघारणीय रूप से उपयोग करें। इसलिए जैव विविधता पर बने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अपनी स्थापना से ही दो अनुच्छेदों द्वारा इनके जैविक संसाधनों के पारंपरिक ज्ञान, व्यवहार और प्रथागत उपयोग का सम्मान, सुरक्षा और प्रोन्नत करने की भूमिका को मान्यता दी है। किन्तु वनाधिकार या कानूनी मान्यता तथा कार्यान्वयन की कमी ऐसे मूलनिवासी समुदायों को अपनी भूमि पर

टिके रहने की क्षमता के बारे में असुरक्षित बना सकती है और वे पूँजीवादी राजकीय सत्ता –कॉर्पोरेट सेक्टर की नापाकमिलीभगत द्वारा भूमि हड़पने का शिकार हो सकते हैं। हममें से हर एक को वैश्विक नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुये मूलनिवासी देशज लोगों के प्रथागत, पारंपरिक वन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए जो हमारे ग्रह के अनुरूप रहते हैं और हमारे आनेवाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए वसुंधरा की रक्षा करते हैं। उनकी आजीविका और जीवनशैली से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन के तरीकों की विरासत और इन ऐतिहासिक वसीयतों से उत्पन्न होने वाली विशेषज्ञता को जुटाना आज और भविष्य में खाद्य और कृषि के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध पत्र वनों एवं जैव-विविधता के संधारणीय प्रबंधन में और जलवायु परिवर्तन के शमन में देशज लोग तथा स्थानीय समुदायों की अहमियत और अपरिहार्यता को उजागर करता है।

मूल शब्द: देशज लोग, जैव-विविधता, वनाधिकार, जलवायु परिवर्तन, संधारणीय प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा

प्रस्तावना

द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट के 2022 संस्करण के अनुसार, पिछले 30 वर्षों में दुनिया ने अपने कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34 प्रतिशत क्षेत्र जो 420 मिलियन हेक्टेयर है खो दिया है और जब तक उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो 2018 और 2050 के बीच अकेले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अनुमानित 289 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वनों की कटाई की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप 169 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। रिपोर्ट के अनुसार 250 उभरते संक्रामक रोगों में से 15 प्रतिशत पशुजन्य (जूनोटिक) बीमारियों को वनों से जोड़ा गया है। 1980 के बाद से रिपोर्ट की गई 30 प्रतिशत नई बीमारियों को निर्वनीकरण या वनों की कटाई और भूमि-उपयोग-परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, डेंगू बुखार और मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों में वृद्धि निर्वनीकरण के साथ जुड़ी हुई है।

अवैध वन्यजीव व्यापार को कम करने, भूमि उपयोग में बदलाव से बचने और निगरानी बढ़ाने के आधार पर पशुजन्य महामारी को रोकने के लिए वैश्विक रणनीतियों की लागत 22 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 31 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई है। उप-सहारा अफ्रीका में लगभग एक अरब लोग 2025 तक चारकोल और ईंधन की लकड़ी जैसे प्रदूषणकारी ईंधन पर निर्भर रहेंगे। संयुक्त रूप से सभी प्राकृतिक संसाधनों की वार्षिक वैश्विक खपत 2017 में 92 बिलियन टन से दोगुनी से अधिक होने की उम्मीद है, जो जनसंख्या के आकार और संपन्नता में वृद्धि के कारण 2060 में 190 बिलियन टन हो गई है। इसमें आगे कहा गया है कि 2017 में 24 बिलियन टन से 2060 तक वार्षिक जैव-भार (बायोमास) निष्कर्षण 44 बिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। मुख्य रूप से भवन-निर्माण और पैकेजिंग के कारण वन-आधारित जैव-भार की मांग में और वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्ट ने वनों और भूमि उपयोग पर ग्लासगो नेताओं की घोषणा की पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि सहित हरित पुनर्प्राप्ति प्राप्त करने और पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए तीन

परस्पर संबंधित मार्गों का सुझाव दिया है।

1. वनों की कटाई को रोकना और वन आवरण को बनाए रखना
2. निम्नीकृत भूमि को बहाल करना और कृषि वानिकी का विस्तार करना
3. वनों का संधारणीय उपभोग और हरित मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमानों के अनुसार, वनीकरण और पुनर्वनीकरण के माध्यम से निम्नीकृत भूमि की बहाली 2020 और 2050 के बीच प्रतिवर्ष वातावरण से 0.9 से 1.5 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभावी ढंग से अधिग्रहण हो सकता है।

स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले लगभग 45% कार्बन को जंगलों में संग्रहित किया जाता है, और वार्षिक मानवजनित कार्बन उत्सर्जन का 25% से अधिक हिस्सा वातावरण से वनों द्वारा अधिग्रहित होता है। इसके अलावा, लगभग 1.3 बिलियन लोग, मुख्यतः विकासशील देशों में, अपने निर्वाह आजीविका और नकद आय के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्रत्यक्ष रूप से जंगलों पर निर्भर हैं। हमारे ग्रह के आवश्यक कार्यों को बनाए रखने और मानव कल्याण में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, वन भूमि को अन्य भूमि उपयोगों जैसे कि फसल भूमि, चारागाह, खनन और शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। वैश्विक स्तर पर जो वन नष्ट हो गए हैं उसमें उष्णकटिबंधीय देशों में वन हानि की सीमा अधिक है, जहां जैविक विविधता के साथ-साथ निर्वाह स्तर की आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता सबसे अधिक है।

वैश्विक निर्वनीकरण से कार्बन उत्सर्जन की एक महत्वपूर्ण मात्रा पैदा हो रही है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन और मानव कल्याण को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय निम्नीकरण में योगदान कर रही है। इसलिए, हाल के वर्षों में विभिन्न पैमानों पर वनों की सटीक निगरानी के प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया गया है। हाल के कुछ अध्ययनों ने दुनिया के कई विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन निम्नीकरण के चालकों एवं अंतर्निहित कारणों को रेखांकित किया है।

वनों की कटाई और वन क्षरण के कुल नौ प्रमुख चालक सूचित किये गए हैं: (1) जंगल की आग, (2) अतिचारण, (3) वन उत्पादों का अरक्षणीय या असन्धारणीय उपयोग, (4) कमजोर वन प्रबंधन प्रथाएं, (5) बुनियादी ढांचे का विकास, (6) शहरीकरण और पुनर्वास, (7) अतिक्रमण, (8) विदेशी आक्रामक प्रजातियों आक्रमण और (9) खनन की पहचान की गई। इसी तरह, जनसंख्या वितरण, स्थानान्तरण, गरीबी, वन उत्पादों पर उच्च निर्भरता, असुरक्षित वन स्वामित्व (जमद, नतम) वनों की कटाई और वन क्षरण के प्रमुख अंतर्निहित कारण हैं। इस तरह विभिन्न जनसांख्यिकीय, सामाजिक आर्थिक, जैव-भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी चालक, व्यक्तिगत तथा सहक्रियात्मक रूप से कार्य करते हुए, विभिन्न कारकों की मानवजनित गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे निर्वनीकरण या वन निम्नीकरण होता है। अंधाधुंध निर्वनीकरण के परिप्रेक्ष्य में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीबीडी), 1992 में अपनी स्थापना से, विशेष रूप से दो धारायें या अनुच्छेद- 8(j) और 10(c) महत्वपूर्ण हैं। इन अनुच्छेदों के माध्यम से देशज लोग एवं स्थानीय समुदायों की भूमिका को मान्यता दी है - जो कानूनी रूप से सरकारों को उनके द्वारा जैविक संसाधनों के पारंपरिक ज्ञान, व्यवहार और प्रथागत उपयोग का सम्मान, सुरक्षा और प्रोन्नत करने के लिए बाध्य करती हैं।

इस भाषा के बावजूद, पारिस्थितिक तंत्र के इन रक्षकों को अभी भी संयुक्त राष्ट्र की शक्ति के गलियारों से काफी दूरी तक हाशिए पर रखा गया है और सीबीडी समझौता वार्ता से अलग कर दिया गया है।

दुनिया की आबादी का केवल 5 प्रतिशत हिस्सा, होने के बावजूद भी देशज लोग पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रबंधक हैं। पारंपरिक देशज लोगों के अधिवास क्षेत्रों में दुनिया की 22 प्रतिशत भूमि की सतह शामिल है, लेकिन पृथ्वी की जैव विविधता का 80 प्रतिशत हिस्सा यहाँ पाया जाता है। कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक वनों का एक तिहाई मुख्य रूप से देशज लोगों, छोटे भूधारकों और स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इनका खाद्य या खानपान भी विशेष रूप से पौष्टिक, जलवायु-लचीले और अपने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जिससे वे जलवायु चुनौती वाले क्षेत्रों में पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत बन जाते हैं।

उनकी आजीविका और उनकी जीवनशैली के तरीके हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संधारणीय तरीकों से भोजन उगाने और प्रकृति के साथ रहने के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इस विरासत और इन ऐतिहासिक वसीयतों से उत्पन्न होने वाली विशेषज्ञता को जुटाना आज और भविष्य में खाद्य और कृषि के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध पत्र वनों एवं जैव-विविधता के संधारणीय प्रबंधन में और जलवायु परिवर्तन के अल्पीकरण में देशज लोग तथा स्थानीय

समुदायों की अहमियत और अपरिहार्यता उजागर करता है।

परिकल्पना

जैव-विविधता, एवं वन पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता, परिष्करण और संवहनीयता के साथ जलवायु परिवर्तन शमन (अल्पीकरण) में सदियों के प्रहरी वन-निर्भर मूलनिवासी-देशज लोगों और स्थानीय समुदायों की अहमियत और अपरिहार्यता पर वैश्विक स्तर पर जैव विविधता पर बने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीबीडी) और संयुक्तराष्ट्रसंघ का खाद्य और कृषि संगठ (एफएओ) ने अनुसंधान के नतीजों के आधार पर मुहर लगा दी है, किंतु देश विदेश की सरकारों में पूँजीवादी राजकीय सत्ता -कॉर्पोरेट सेक्टर की नापाक साठ-गांठ के चलते निर्वनीकरण और जैवविविधता की अपरिमित हानि के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में तेजी से बढ़ोतरी जारी है।

क्रिया-विधि

गुणात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से मानवीय अनुभव पर आधारित होता है, जिसमें परिवर्ती राशि को परिमाणित किए बिना धारणाओं और सैद्धांतिक जानकारी का उपयोग किया जाता है। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत लेख गुणात्मक विषय-वस्तु विश्लेषण के दायरे में असंरचित और गैर-संख्यात्मक डेटा पर निर्भर रहकर समस्या के सटीक स्वरूप को हल करने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं अनुसंधान कर्ताओं के संदर्भ सूचीबद्ध प्राथमिक एवं प्रकाशित साहित्य या डेटा का समीक्षात्मक अध्ययन है।

विचार-विमर्श

मानव जनसंख्या में वृद्धि के लिए भोजन, आवास और अन्य वस्तुओं के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप वन क्षेत्रों को कृषि या अन्य भूमि उपयोग में परिवर्तित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय निर्वनीकरण के कारणों का विश्लेषण करने वाले 140 से अधिक आर्थिक मॉडलों के संश्लेषण से पता चला है कि अधिक सड़कें, उच्च कृषि मूल्य, कम मजदूरी और गैर-कृषि रोजगार की कमी से अधिक वनों की कटाई होती है। हालांकि, निर्वनीकरण के चालक भौगोलिक स्थानों और ऐतिहासिक संदर्भों में भिन्न होते हैं। पिछले 50 वर्षों में, वनों की कटाई के कारक बदल गए हैं। ऐतिहासिक रूप से, जंगलों को फसलों या पशुधन के लिए साफ किया गया था, और छोटे किसानों को निर्वनीकरण का एक प्रमुख चालक माना जाता था। इसके विपरीत, 1990 के बाद से आर्थिक वैश्वीकरण के बाद, कृषि विस्तार, सड़क निर्माण, लकड़ी की निकासी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जंगलों को बड़े पैमाने पर साफ कर दिया गया है। ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे कई देशों में पशुपालन, सोयाबीन और ताड़ के तेल के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर कृषि विस्तार और इमारती लकड़ी की कटाई निर्वनीकरण का

कारण बन रही है।

लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ का खाद्य और कृषि संगठन (FAO) भुखमरी के उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन के समाधान प्रदान करने में देशज लोगों एवं स्थानीय समुदायों को अनमोल साझेदार मानता है। उनका मानना है कि देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा और उनसे मदद मांगे बिना जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए दीर्घकालिक समाधान कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार देशज लोग निम्नलिखित वनों एवं जैव-विविधता के संधारणीय प्रबंधन तरीकोंसे दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर रहे हैं।

इतिहास के झरोखे से देखेंगे तो तो सदियों से, देशज लोगों ने कृषि तकनीकों का विकास किया है जो अतिविषम जलवायु के अनुकूल हैं, जैसे कि एंडीज की ऊँचाई, कैन्या के सूखे घास के मैदान या उत्तरी कनाडा की अत्यधिक ठंड। ये समय-परीक्षणित तकनीकें, जैसे मिट्टी के कटाव या भू-क्षरण को रोकनेवाला वेदिकाकरण (terracing) या तैरते हुए बगीचे (फ्लोटिंग गार्डन्स) जो बाढ़ वाले खेतों का उपयोग करते हैं, का मतलब है कि वे तेजी से तीव्र मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन द्वारा लाए गए तापमान परिवर्तन के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हैं। देशज लोग स्वयं को प्रकृति से जुड़े हुए और उसी व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखते हैं जिसमें वे रहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को साझा संपत्ति माना जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। जंगलों और नदियों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करके, देशज लोग एवं स्थानिक समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की गंभीरता को कम करने में मदद करते हैं।

वर्तमान युग में दुनिया मुख्य फसलों के एक छोटे गिने-चुने समूह पर बहुत अधिक निर्भर है जिसमें सिर्फ गेहूँ, चावल, आलू और मक्का दैनिक खपत का 50 प्रतिशत कैलोरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्विनोआ, ओका और मोरिंगा जैसी पौष्टिक, देशी फसलों के साथ, देशज लोगों की खाद्य प्रणालियाँ बाकी मानवता को अपने संकीर्ण भोजन आधार का विस्तार करने में मदद कर सकती हैं। क्योंकि कई देशज लोग अत्यधिक अतिविषम जलवायु में रहते हैं, उन्होंने ऐसी फसलों को चुना है जिन्हें भी अनुकूलित करना पड़ा है। देशज लोग अक्सर फसलों की देशी प्रजातियाँ उगाते हैं जो स्थानीय संदर्भों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित होती हैं और अक्सर सूखे, ऊँचाई, बाढ़ या अन्य मौसम की चरम स्थितियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं। खेती में अधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ये फसलें अब बदलते, अधिक अतिविषम जलवायु का सामना कर रहे खेतों का लचीलापन बनाये रखने में मदद कर सकती हैं।

खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए जैव विविधता का संरक्षण अत्यावश्यक है। पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए आनुवंशिक पूल (वंशाणु समुच्चय) जंगलों, नदियों और झीलों और चरागाहों में पाया जाता है। स्वाभाविक रूप से

संधारणीय जीवन जीते हुए, देशज लोग प्रकृति में पौधों और जानवरों की 80 प्रतिशत जैव विविधता का भरण पोषण करते हुए इन स्थानों को संरक्षित करते हैं। देशज लोगों ने अपने पर्यावरण का सम्मान करते हुए उसके साथ समुचित होने के लिए अपनी जीवन शैली को अनुकूलित किया है। पहाड़ों में, देशज लोगों की जीवन प्रणालियाँ मिट्टी का संरक्षण करती हैं, भूक्षरण को कम करती हैं, पानी का संरक्षण करती हैं और आपदाओं के जोखिम को कम करती हैं। प्रक्षेत्र-चरागाह (रेंजलैंड्स) में, देशज चरवाहा समुदाय मवेशियों के चरने और फसल को टिकाऊ तरीके से प्रबंधित करते हैं जो प्रक्षेत्र-चरागाह की जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। अमेज़न में पारिस्थितिक तंत्र में सुधार होता है जब देशज लोग उनमें निवास करते हैं। जैव विविधता के तेजी से हो रही गिरावट को धीमा करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक और सभी क्षेत्रों में मौलिक प्रणाली-व्यापी पुनर्गठन जैसे परिवर्तनकारी बदलावों को जैव विविधता नीतियों के डिजाइन, और कार्यान्वयन में लागू करना जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) के लिए अत्यावश्यक है।

इस परिवर्तनकारी बदलाव के 'परिप्रेक्ष्य' में, देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों और जैव विविधता नीति में उनकी अग्रप्रस्तुति की आवश्यकता है। दुनिया की अधिकांश जैव विविधता अब देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक स्वामित्व, प्रबंधन, उपयोग और/या कब्जे वाले भू-परिदृश्यों और समुद्री परिदृश्यों में भलीभाँति मौजूद है। इसके अलावा, संसाधनों की निकासी के बढ़ते दबाव और देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बावजूद, वो अपने क्षेत्रों और संसाधनों की पुरजोर रक्षा कर रहे हैं। सक्षिप्त में देशज लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित क्षेत्रों में जैव विविधता कहीं और की तुलना में अधिक धीरे-धीरे घट रही है। देशज या मूलनिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों के पास यथार्थवादी और प्रभावी जैव विविधता लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक ज्ञान है जो एक साथ स्थानीय आजीविका में सुधार करते हैं। उनकी प्रकृति की अवधारणा सीबीडी के 2050 के 'प्रकृति के साथ समरसता या तालमेल में रहने' के दृष्टिकोण को ना सिर्फ प्रकट करती है, पर उसे पोषित भी करती है। इसलिए जैव विविधता नीति निर्माण में उनकी भागीदारी मानव और देशज लोगों के अधिकारों की मान्यता में योगदान करती है। सक्षिप्त में देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के लिए क्षेत्राधिकार तथा संसाधनों के अपने मान्यता प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम होने के लिए जैव विविधता नीति में जुड़ाव या अनुबंध आवश्यक है।

देशज लोग एवं स्थानीय समुदायों को ऐतिहासिक रूप से उन सभी महत्वपूर्ण चर्चाओं और निर्णयों से बाहर रखा गया है जिनमें वे निवास करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों से घिरे क्षेत्र के वे मूलनिवासी हैं। इसका परिणाम परिरक्षण नीतियों के विकास में होता है जो भूमि हथियाने, प्रदूषण में

वित्तीय संसाधनों के असमान आवंटन में और अन्य दबाव वाली सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। पार्ष्वीकरण युग समाप्त होना चाहिए। देशज लोग एवं स्थानीय समुदायों के प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण के महत्व पर यह नया आख्यान स्थानीय जैव विविधता आउटलुक- 2 के प्रकाशन से अनुसरण करता है, वन पीपल्स प्रोग्राम के नेतृत्व में एक रिपोर्ट जो जैव विविधता के संरक्षण में अग्रणी देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के 50 मामलों के अध्ययनों (केस स्टडीज) का दस्तावेजीकरण करती है। लगभग हर दिन, परिरक्षण में देशज नेतृत्व के अधिक उदाहरण दर्ज किए जाते हैं – जो यह निःसंदेहता से साबित करते हुए कि जब अधिकारहीन लोगों के पास अपनी भूमि का पूर्ण शासन होता है तो यह जैव विविधता के लिए एक 'गेम चेंजर' हो सकता है।

अनेक अध्ययनों में यह उद्बोधक तौर पर देखा गया है कि देशज लोग एवं स्थानीय समुदायों के अधिवास के क्षेत्रों में इस क्षेत्र के बाहर अन्य भूमि की तुलना में काफी अधिक प्रजातियों की आबादी होती है। वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्क देते हैं कि देशज लोगों के लिए अपनी पारंपरिक आजीविका को बनाए रखने और देश की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बड़े, कानूनी रूप से निर्दिष्ट क्षेत्र आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में, इन अधिकारहीनों भूमि का भू-धारण अधिकार या पट्टेदारी (सुधृति) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक प्रतिफल-उन्मुख रूप है, जो शायद सबसे प्रभावी रूप जो हमारे पास उपलब्ध है। हमें उन गंभीर खतरों को भी स्वीकार करना चाहिए जो देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के सामने हैं क्योंकि बहु-अरब डॉलर के निगम भूमि से अधिक से अधिक लाभ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। परिरक्षण को लोगों और प्रकृति के लिए काम करना चाहिए, दोनों को पर्यावरणीय नुकसान के चालकों से बचाना चाहिए। और इसका मतलब है कि 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढांचे के केंद्र में देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के भूमि स्वामित्व अधिकारों को रखना।

उपसंहार

जैवविविधता को बचाने के लिए देशज लोग और स्थानीय समुदायों को सशक्त करना एक बेहतर विकल्प है क्योंकि दुनिया भर में आज भी एक बड़ा हिस्सा इन वनवासियों की वजह से ही इंसानी महत्वाकांक्षा और लालच की भेंट नहीं चढ़ा है। यह लोग इन क्षेत्रों के वास्तविक प्रहरी हैं, जिन्होंने प्रकृति के साथ मिलकर जीना सीख लिया है, जो हम आज भी नहीं सीख पाए हैं। इनके अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने से ही हमारे वनों को सुरक्षित रखा जा सकता है, और प्राकृतिक दुनिया को अपनी लचीलापन (तन्यकता) वापस लाने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी रक्षा करने में मदद मिल सकती है। देशज लोगों की संस्कृति और आजीविका वन पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई है; जहाँ उनका जैविक अनुकूलन, उनके आध्यात्मिक विश्वासों के साथ, यह मांग करता है कि वे जैवविविधता का संरक्षक बने रहे और वनों का संधारणीय रूप से उपयोग करें। देशज लोग और स्थानीय समुदायों के दुनिया की 50%से अधिक भूमि पर पारंपरिक रूप से कब्जा और उपयोग है, लेकिन दुनिया की केवल 10% भूमि के वो कानूनी रूप से मालिक है। कानूनी मान्यता की कमी ऐसे समुदायों को अपनी भूमि पर टिके रहने की क्षमता के बारे में असुरक्षित बना सकती है, और खनन, लॉगिंग या कार्बन क्रेडिट से अवसरों से लाभ चाहने वालों द्वारा भूमि हड़पने का शिकार हो सकती है।

अंततः हममें से हर एक को वैश्विक नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम नए वैश्विक संधारणीय विकास एजेंडा के अवसर का उपयोग नीतियों की वकालत करने और निर्धारित करने के लिए करें जिसमें हमारे वसुधरा के सभी लोग शामिल हों। हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए और एक ऐसे वातावरण का पोषण करना चाहिए जो संधारणीय विकास को बढ़ावा दे। हमें मूलनिवासी देशज लोगों की रक्षा करनी चाहिए जो हमारे ग्रह के अनुरूप रहते हैं, हमारे भविष्य के लिए इसकी रक्षा करते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ –

1. **Karl Burkart (2022)** Indigenous land rights take center stage in a new global framework for biodiversity conservation (commentary) *mongabay.com* <https://www.google.com/amp/s/news.mongabay.com/2022/03/indigenous-land-rights-take-center-stage-in-a-new-global-framework-for-biodiversity-conservation/amp/>
2. **Reyes-García, V., Fernández-Llamazares, Á., Aumeeruddy-Thomas, Y. et al. (2022)** Recognizing Indigenous peoples' and local communities' rights and agency in the post-2020 Biodiversity Agenda. *Ambio* Vol. 51, Pp:84–92. <https://doi.org/10.1007/s13280-021-01561-7>
3. 6 ways indigenous peoples are helping the world achieve #ZeroHunger FAO UN <https://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/1028010/>